

निवेशकों का भरोसा है प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी: सीएम योगी

सीएम ने निवेश मित्र-3.0 का किया शुभारंभ, बोले-वैश्विक अनिश्चितता के दौर में यूपी बना भरोसेमंद गंतव्य

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** प्रदेश में निवेशकों के लिए निवेश की प्रक्रिया आसान हो, निवेशकों को अलग-अलग विभागों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को निवेश मित्र पोर्टल-3.0 का उद्घाटन किया। साथ ही यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डिवेलपमेंट स्कीम का भी शुभारंभ किया। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा

कंपनियों को वितरित किया 2781 करोड़ का इन्सैटिव

कि प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में पारदर्शी नीतियों, सख्त कानून-व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग-अनुकूल माहौल के जरिए अपनी पहचान को पूरी तरह बदला है। यही कारण है कि जो निवेशक पहले प्रदेश आने से हिचकते थे, आज वही यहां निवेश के लिए आगे आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। निवेशकों का विश्वास ही प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है। इसी विश्वास को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

उद्योगों के संचालन में बाधा या अराजकता बर्दाश्त नहीं : कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि



कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य, नंद गोपाल गुप्ता नंदी समेत कई मंत्री-अफसर भी मौजूद रहे।

कहीं ट्रेड यूनियन या अन्य किसी नाम पर उद्योगों को बाधित करने की कोशिश की जाती है, तो वह स्वयं तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित डीएम और एसपी को निर्देश देकर ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करवाते हैं, ताकि निवेश और उद्योगों का माहौल प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर की 'लाल इमली' मिल जैसे उदाहरण बताते हैं कि कैसे पहले ट्रेड यूनियनों और गलत नीतियों के कारण एक समय का प्रमुख टेक्सटाइल हब बंद हो गया और हजारों परिवार प्रभावित हुए।

'पहले निवेश के प्रस्ताव पर हंसे थे निवेशक' : मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में जब सरकार बनी तो निवेश के लिए जब उद्यमियों को यूपी आने का आमंत्रण दिया जाता तो वे हंसे थे। कई लोग तो पहले से

ही यहां न आने का संकल्प लेने की बात करते थे। उस समय प्रदेश की छवि इतनी खराब थी कि निवेश की बात करना भी असहज लगता था। इस नकारात्मक धारणा के पीछे दो प्रमुख कारण थे। पहला पहचान का संकट और दूसरा माफिया व आपराधिक गिरोहों का प्रभाव, जो हर जिले और थाने में समानांतर सत्ता चलाकर उद्यमियों, व्यापारियों, महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। तब हमने इस माफिया की कमर तोड़ने, इसे पूरी तरह कुचलने का निर्णय किया। हमने तय किया कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे।

62 कंपनियों को निवेश के लिए जारी हुई एलओसी : कार्यक्रम के दौरान

विभिन्न पॉलिसी के तहत 45 कंपनियों को इंसैटिव वितरण किया। वहीं, 62 कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) दी गई। इसके अलावा 52 कंपनियों को 2781 करोड़ रुपये का सब्सिडी चेक दिया गया। इन प्रस्तावों के जमीन पर उतरने से करीब 50 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

धारा-80 की जटिलता को किया गया खत्म : मुख्यमंत्री ने बताया कि 'इंज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस' को और मजबूत करते हुए धारा 80 के तहत लैंड यूज की जटिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। अब मास्टर प्लान के तहत नक्शा पास होते ही लैंड यूज स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। अलग से किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी। साथ ही 'निवेश मित्र 3.0' को लॉन्च

कर 43 से अधिक विभागों की 530 सेवाओं को सरल बनाकर 200 से कम सेवाओं में समेकित किया गया है। इसमें पैन आधारित सिंगल यूजर आईडी, एआई चैटबॉट, रियल-टाइम ट्रेकिंग, ऑटोमेटेड अलर्ट और ऐड-टू-ऐड ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

2012-17 के बीच मात्र 16 एलओसी, 9 वर्षों में 3367 जारी : सीएम ने कहा कि 2012 से 2017 के बीच मात्र 16 एलओसी जारी हुए थे, वहीं पिछले 9 वर्षों में 3367 एलओसी जारी किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश एक नए औद्योगिक दशक में प्रवेश कर चुका है, जहां रिकॉर्ड निवेश और तेज परियोजना क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है। इस मौके पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि यूपी आज विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के लिए पसंदीदा गंतव्य बन चुका है।

कार्यक्रम के दौरान आईटी ऐंड इलेक्ट्रॉनिक विभाग के मंत्री सुनील कुमार शर्मा, राज्य मंत्री औद्योगिक विकास जसवंत सैनी, प्रदेश के अवस्थापना औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान बाबूलाल मीणा, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे।